(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पटसन मिलों का गैर-सरकारीकरण

341. **श्री अजीत जोगी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की कतिपय पटसन मिलों के गैर-सरकारीकरण का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन पटसन मिलों के गैर-सरकारीकरण से कितने कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) उक्त कर्मकारों के हितों की रक्षा हेतु क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

धागे के मूल्यों में वृद्धि

342. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1995 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "हाइक इन यार्न प्राइसेज रेन्डर्स वीवर्स आइडल" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूती धागे के मूल्यों में नवम्बर, 1993 से लेकर अब तक लगभग शत प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सच्चाई क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि हथकरघा उद्योग के बुनकरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से बुनकरों को लाभ नहीं हो रहा है ; और

(ङ) देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले असंगठित हथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों को सरकारी सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु क्या-क्या प्रबंध किए गए हैं, साथ ही उन स्तरों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये प्रबंध किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हथकरघा उद्योग में प्रयोग होने वाले सूती हैंक यार्न के मूल्यों में नवम्बर, 1993 से अप्रैल 1994 के दौरान वृद्धि हुई और मई 1994 से अक्तूबर, 1994 के दौरान इसके मूल्य लगभग स्थिर रहे । इसके उपरांत कपास के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण सूती हैंक यार्न के मूल्यों मे वृद्धि हुई । तथापि नवम्बर, 1993 से आज तक यह वृद्धि 100 प्रतिशत नहीं थी । सूती हैंक यार्न के मूल्यों का काऊंट और महावार विवरण अनुपत्र के रूप में संलग्न है । [**देखिए परिशिष्ट** 173, अनुपत्र स० 7]

(घ) जी नहीं ।

(ङ) हथकरघा सहकारिताओं में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का लाभ बुनकरों को देने के उद्देश्य से भारत सरकार असंगठित हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाने के लिए वर्ष 1993-94 से हथकरघा, विकास के

योजना आरंभ की है । इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में 9 मार्च, 95 तक 702 हथकरघा विकास केन्द्रों और 161 उत्कर्ष राई इकाईयों की मंजूरी दी गई है । इसके अतिरिक्त असंगठित हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकर अन्य वर्तमान योजनाएँ जैसे विभिन्न शिल्प मेलों में भाग लेकर अपने उत्पादों के विपणन के लिए सहायता ले सकते हैं और देशभर में फैले 23 बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से डिजाइन, बुनाई, प्रोसेसिंग और रंगाई तकनीक में अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने और अनुसंधान व विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

Raw Jute Market

343. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government did not allow Jute Corporation of India to intervene in the raw jute market though prices of raw jute remain within the range of purchase;

(b) whether it is also a fact that Government did not release funds for purchase of raw jute; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No Sir. JCI's mandate is that it should purchase whatever quantity of jute is offered to it by growers at Minimum Support Prices. This year prices have generally remained well above Minimum Support Price levels.

(b) and (c) Government releases funds to JCI as subsidy on losses incurred by it on sale of raw jute procured under Price Support Operation. During the current year Government has released adequate funds to JCI.

Export of polyseter yarn and fabric

344. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) which are the organisations in the country which have been entrusted with the responsibility of export of cotton particularly textuaries polyester yarn and knitted polyester fabric;

(b) what is the quantum and value of above mentioned items in respect of which such organisations had signed agreements with foreign countries for their exports during the years 1992-93, 1993-94 and 1994—95 till date;

(c) what are the future prospects of exports of above mentioned items indicating the orders booked (country-wise) for the years 1994-95, 1995-96 and 1996-97 with quantity and value thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No specific organisation is entrusted with the sole responsibility of exporting cotton or yarn or fabrics and such exports are effected by the interested exporters/organisations themselves.

(b) The exporter/organisation wise details of export agreements entered into between the Indian exporters and the foreign buyers is not mained.

(c) The current export trends indicate that there are good prospects for exports of these items in future.

Modernisation and revival plan of NTC

345. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in Cabinet approval to the unanimous 8-point agreement on moderisation and revival of the NTC mills arrived